शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 10 – 17 जून 2024 मूल्य पांच रूपये

सुक्खू और अनुराग की प्रतिष्ठा का टैस्ट होंगे यह उप चुनाव

- हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में है दो उपचुनाव
- यदि निर्दलीयों के त्यागपत्र पहले ही स्वीकार हो जाते तो प्रदेश इस खर्च से बच जाता

शिमला/शैल। प्रदेश में फिर तीन उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि तीनों निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र बाद में स्वीकार किये गये। जबकि इन लोगों ने भी फरवरी में हुये राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान करने के बाद अपनी विधायकी से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गये थे।

लेकिन इनके त्यागपत्रों को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर उनके मामले को लटका दिया गया था। दो कांग्रेस विधायकों अवस्थी और गौड़ की शिकायत पर आशीष शर्मा और बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के खिलाफ बालूगंज थाना में एक मामला तक दर्ज कर दिया गया। यही नहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की शिकायत पर दल बदल कानून के तहत भी मामला चलाया गया। यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने स्वेच्छा से अपनी विधायकी से त्यागपत्र नहीं दिया है। पुलिस जांच का मुख्य बिन्दु ही इनं त्यागपत्रों और फिर भाजपा में शामिल होने के पीछे धन बल का दबाव रहना बनाया गया था। लेकिन इन मामलों के लंबित रहते ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिये जाने से कांग्रेस के विधायकों और राजस्व मंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों की धार स्वत: ही कुन्द होकर यह आरोप स्वत: ही सत्ता पक्ष को चुभने के कगार पर पहुंच गये हैं। भाजपा ने इनके पार्टी में शामिल होते ही इन्हें उनके क्षेत्रों से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब इन उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा ने उनकी उम्मीदवारी की पुष्टि भी कर दी है। अब इनके खिलाफ जब यह सवाल उठाया जा रहा है कि इन्होंने विधायकी से त्यागपत्र क्यों दिये और प्रदेश के खजाने पर उपचुनावों का बोझ क्यों डाला? अब इस सवाल का बड़ा हिस्सा स्वत: ही उस बिन्दु की ओर मुड़ जाता है की इनके त्यागपत्रों की स्वीकृति को लटकाये क्यों रखा गया है। इनके खिलाफ दायर मामले मामलों का कोई फैसला आने से पहले ही यह त्यागपत्र इसलिये स्वीकार कर लिये गये क्योंकि इनके खिलाफ प्रमाणिक रूप से ऐसा कुछ भी शायद रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा था जिसके आधार पर इन्हें दण्डित किया जा सकता। यदि यह उपचुनाव भी पिछले उप चुनावों के साथ ही होने दिये जाते तो आज अतिरिक्त खर्चे से बचा जा सकता था। इसलिए इन उपचुनावों के लिये उन्हें दोषी ठहरने का तर्क आत्मघाती हो सकता है। लोकसभा की चारों सीटें भाजपा द्वारा जीतने के बाद भी हिमाचल को केंद्रीय मंत्री परिषद में स्थान नहीं मिला है।

अनुराग ठाकुर लगातार पांच बार लोकसभा जीत गये हैं लेकिन इस बार मंत्री नहीं बन पाये हैं क्योंकि उनके ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से भाजपा तीन विधानसभा उपचुनाव हार गयी। जबकि इन तीनों स्थानों पर लोकसभा के लिये भाजपा को बढ़त मिली है। यदि जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार की मजबूती के लिये कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है तो उस तर्क से तो सभी छ: सीटों पर कांग्रेस की जीत होनी चाहिये थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस उपचुनाव में भाजपा की चारों सीटों पर हार अनचाहे ही अनुराग-धूमल के नाम लगायी जा रही है और इस हार के कारण ही अनुराग शायद मंत्री परिषद से बाहर गये हैं। अब फिर तीन में दो उप चुनाव अनुराग के ही संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं। इसलिए यह उपचुनाव एक तरह से मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह और अनुराग ठाकुर के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएंगे। क्योंकि एक को यह प्रमाणित करना है कि उसने पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई आचरण नहीं किया है। दूसरे को यह सिद्ध करना है कि जनता कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू के साथ है। वैसे लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में कांग्रेस को मिली हार स्वत: ही दावे पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है।

राज्यपाल ने किया चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का शुभारम्भ किया। इस इस तरह के आयोजन हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मोत्सव में आयोजित किए

अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने कहा कि जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हिमाचल की लोक कला के विविध रंगों से अवगत करवाते हैं।

शिमला के उपायुक्त एवं शिमला ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर लेडी गवर्नर, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक हरीश जनारथा को भी सम्मानित किया।

राज्यपाल ने सांस्कृतिक संध्या का भी आनंद उठाया। 'नाटी किंग' कुलदीप शर्मा की प्रस्तुति सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण रही। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में छः नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक राकेश कालिया, विवेक शर्मा, कैप्टन सेवानिवृत्त रंजीत राणा, अनुराधा राणा, सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण करने के उपरांत अब सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई व शुभकामनाएं दीं।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा का प्रदेश में सरकार बनाने का दावा विफल हो गया है क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उपचुनावों में कांग्रेस के चार विधायकों को चुना है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या 38 होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखेगी और इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में चार विधायकों को हराकर राज्य के लोगों ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को नकारा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए शीघ्र ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने विनियमन एवं निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते

हुए प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 364 तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें से 184 निजी संस्थान हैं। उन्होंने विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निजी संस्थानों के विनियमन एवं निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विभाग को संसाधनों को सुव्यवस्थित करने तथा दक्षता में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई एवं बहुतकनीकी महाविद्यालयों को एक ही परिसर में एकीकृत करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को युवाओं के लिए बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगोन्मुखी एवं रोजगार प्रदान करने वाले आधुनिक पाठयक्रम आरम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों में आवश्यक कौशल एवं उपलब्ध प्रशिक्षित श्रमशक्ति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदक उपलब्ध रोजगार अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने विभाग को विशेष पाठयक्रमों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने के लिए अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में 1077 संकाय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में नवीनतम शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकियों से अवगत रहने के लिए प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक प्रशिक्षुता नीति तैयार करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत छात्रों को विभिन्न सरकारी विभागों में एक वर्षीय प्रशिक्षुता पाठयक्रम प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक के दौरान एक प्रस्तुति भी दी गई।

मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव तकनीकी शिक्षा प्रियतु मंडल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश के सभी जिलों में 85 स्थलों पर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन

शिमला/शैल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आज प्रदेश के सभी जिलों में 85 स्थलों पर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य सचिवालय शिमला में इसके लिए कमांड सेंटर स्थापित किया गया था। कमांड सेंटर में विभिन्न जिलों में की जा गई मॉकड्रिल की निगरानी की गई।

इस दौरान कमांड सेंटर शिमला में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे।

उन्होंने उपायुक्तों से वर्चुअल माधम से बातचीत की और धरातल पर किए जा रहे अभ्यास के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संचार स्थापित करने और प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम किया जाए ताकि जान-माल का जोखिम कम से कम हो।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम समय में बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधा लोगों तक पहुंचे। उन्होंने मनाली, कुल्लू, मंडी और लाहौल जैसे आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में सैटेलाइट फोन के माध्यम से संचार स्थापित करने पर भी बल दिया। बागवानी मंत्री ने कहा कि रेडियो आधारित संचार आपात स्थित में सहायक सिद्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान संयुक्त सचेतक प्रणाली सीएपी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रणाली से आपदा से पूर्व ही लोगों को मोबाइल पर संदेश भेजकर दूसरी जगह स्थानांरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में कई जगहों पर वेदर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे जिससे आपदा का जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। जगत सिंह नेगी ने हिमस्खलन से संभावित खतरे को लेकर सेंसर तकनीक का इस्तेमाल करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में श्रमशक्ति को भी बढ़ाया जाएगा।

इस अवसर पर उन्होंने आपदा के प्रति जागरुकता सामग्री का विमोचन किया। नेगी ने आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र ईओसी का भी दौरा किया।

विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने जगत सिंह नेगी को आपदा के दौरान सचेत, आरएमएस रिलीफ, समर्थ, मेघदूत, दामिनी, मौसम और ड्रोन मैपिंग एप्पीलीकेशन के महत्व के बारे में जानकारी दी।

एनडीआरएफ के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुधीर बहल ने सभी जिलों से मॉकड्रिल के दौरान पेश आई चुनौतियों के बारे में जानकारी ली और समस्याओं के समाधान के सुझाव भी लिए।

विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने सभी जिलों को शीघ्र मॉकड्रिल की रिपोर्ट बनाकर प्रेषित करने का आग्रह किया।

इस दौरान एनडीआरएफ 14वीं बटालियन के कमाडेंट बलजिंद्र सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी, एसडीआरएफ के एसपी अर्जित सेना ठाकुर और सभी विभागों से वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत 14 बच्चों का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की विश्व स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा पूरी हो रही हैं। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के अनाथ बच्चों को कॉन्वेंट और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने में मील पत्थर साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिशु सुधार गृह की तीन अनाथ लड़कियों को कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल, शिमला में दाखिला मिल गया है और उनके लिए परिवहन सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, शिशु सुधार गृह के पांच बच्चों को दयानंद पब्लिक स्कूल, शिमला जबकि चार अनाथ बच्चों को पाइनग्रोव स्कूल, सोलन और दो बच्चों को डीएवी स्कूल, सुंदरनगर, जिला मंडी में दाखिला दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन कर रही है। संबंधित विभाग को राज्य के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में और अधिक अनाथ बच्चों को दाखिला दिलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 48 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15.52 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, 17 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 7.02 लाख रुपये, एक बच्चे को कुशल विकास के लिए 17500 रुपये, तीन बच्चों को स्टार्ट-अप परियोजनाओं के लिए 6 लाख और दो अनाथ बच्चों को वर्ष 2023-24 के लिए भूमि आवंटित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 68 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 28.30 लाख रुपये, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 48 बच्चों को 26.95 लाख रुपये, दो अनाथ बच्चों को कौशल विकास के लिए 3.13 लाख रुपये और चार लाभार्थियों को स्टार्ट-अप परियोजनाओं के लिए 7.45 लाख रुपये दिए गए हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: त्रटचा शर्मा

प्रदेश विश्वविद्यालय में एससीए चुनाव करवाने के लिए संभावनाएं तलाशेगी सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व विद्यार्थियों (डेकाडल चैप्टर ऑफ 90') के दो दिवसीय 'मैत्री' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 'मैत्री' के इंटरनेशनल चैप्टर का भी शुभारंभ किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए भी कई अहम कदम उठा रही है। पहली कक्षा से ही सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू कर दी गई

है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों से भी जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में बदलाव लाने जा रही है, ताकि नई तकनीक पर आधारित नये पाठयक्रम शुरू किए जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को देश का सबसे सम्पन्न राज्य बनाना चाहती है। प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और वर्तमान सरकार वर्ष 2032 तक राज्य को सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व छात्र एसोसिएशन के भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर तीन पुस्तकों का विमोचन भी किया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा की पुस्तक 'जूनी' पुस्तक का विमोचन किया जिसमें एक प्रेम कहानी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जेपी शेखपुरा की 'मैं और मेरी एचपी यूनिवर्सिटी' और 'यादें बुरांस की' पुस्तक का विमोचन भी किया। यादें बुरांस की पुस्तक में 450 लेखकों ने अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सक्षम चार विद्यार्थियों को एसोसिएशन का आजीवन फ्री मेम्बरशिप सर्टिफिकेट भी प्रदान किया।

विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विश्वविद्यालय के उनके पुराने साथी हैं। उस समय विश्वविद्यालय का माहौल बहुत अच्छा था और सभी एक-दूसरे की सहायता करते थे। विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को हर संभव मदद प्रदान की जाती थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लगभग 25 छात्र नेता वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में तीन विचारधाराओं का संगम होता है और यह संघर्ष की भूमि है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सहित हजारों पूर्व विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

इससे पहले, पूर्व छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. चंद्रमोहन परशीरा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि एसोसिएशन जिला शिमला के नेरी क्षेत्र को गोद लेकर उसमें अधोसंरचना विकास करेगी।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया, उपायुक्त अनुपम कश्यप और देश-विदेश से आए विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी भी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही उन्हें बाहरी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों की संस्कृति को समझने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि अनुभव से परिपक्वता और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रहकर ही राजनीतिक संघर्ष सीखा है। विश्वविद्यालय में बिताये लम्हों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी कई अविस्मरणीय स्मृतियों को भी साझा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश विश्वविद्यालय में एससीए चुनाव करवाने की संभावनाएं तलाशेगी क्योंकि ये चुनाव विद्यार्थियों को समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को लोभ और मोह से बचना चाहिए और समाज की निस्वार्थ सेवा करने की भावना आत्मसात करनी चाहिए।

पोस्ट कोड 903 और 939 के मामलों को मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी उप-समिति

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मत्रिमण्डलीय उप-समिति की तीसरी

बैठक आयोजित की गई। इस उप-समिति का गठन तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से आयोजित विभिन्न भर्तियों के लंबित परीक्षा परिणामों से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए किया गया है।

उप-समिति ने पोस्ट कोड-817 के अनुरूप पोस्ट कोड-903 जेओए आईटी और पोस्ट कोड-939 जेओए आईटी के परिणाम घोषित करने की सिफारिश की है। हालांकि पोस्ट कोड-903 जेओए आईटी के कुल 82 पदों में से 5 पद तथा पोस्ट कोड-939 जेओए आईटी के 295 पदों में से 11 पद रिक्त रहेंगे जिनपर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति दोनों पोस्ट कोड के मामलों को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

इस अवसर पर उप-समिति के सदस्य राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने भविष्य में विभिन्न परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन के लिए उपाय सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

प्रधान सचिव कार्मिक व मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के सदस्य सचिव आर.डी.नजीम, सचिव विधि एस. के.लगवाल, एडीजी.एस.वी. और एससीवी सतवंत अटवाल त्रिवेदी, अध्यक्ष एपीआरसीए आर.के.परुथी, एसपी (एसआईयू) सतर्कता डॉ. रमेश छाजटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

धनी राम शांडिल ने जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनने पर दी बधाई

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने एवं स्वास्थ्य मंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के जिला बिलासपुर से संबंध रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में मिली जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए हिमाचल के हितों की रक्षा करेंगे।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय को अपनाते हुए अनेक कल्याणकारी फैसले लिए हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरम्भ करने के साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिमाचल सरकार प्रदेश के लोगों को घर-द्वार पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वकांक्षी कदम उठाए हैं और उम्मीद व्यक्त की कि हिमाचलवासियों को श्रेष्ठतम चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश में चल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ करने की अपील की और प्रदेश में केंद्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं को गति प्रदान करने का आग्रह किया।

शिक्षा मंत्री ने पराशर ऋषि की तपोस्थली पराशर झील में आयोजित जिला स्तरीय सरनाहुली मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पराशर ऋषि की तपोस्थली पराशर झील में आयोजित जिला स्तरीय सरनाहुली मेले का शुभारम्भ किया। उन्होंने पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त द्रंग विधानसभा के चार स्कूलों घ्राण, देयोरी, बागी कटौला और कथोग स्कूल के भवनों का शिलान्यास किया।इन पर 17 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी उतनी मुहैया करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घ्राण के निर्माण पर 5.41 करोड़ रुपये, दियोरी स्कूल के निर्माण पर 4.24 करोड़ रुपये, बाग्गी कटौला स्कूल भवन पर के निर्माण पर 3.87 करोड़, कथोग स्कूल के निर्माण के लिए 3.53 करोड़ खर्च होंगे।

उन्होंने इस अवसर पर 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्वाड़ स्कूल भवन का उदघाटन भी किया। उन्होंने बताया कि इन स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए लिए प्रथम किश्त के तौर पर लोक निर्माण विभाग को 6 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूल भवनों का निर्माण निश्चित समय में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ठाकुर कौल सिंह के आग्रह पर कोटा धार में तत्काल प्राथमिक पाठशाला खोलने की घोषणा भी की।

उन्होंने बताया कि सभी क्षतिग्रस्त स्कूलों मं प्रथम चरण की किश्त जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछली बरसात में जिला में 17 प्राथमिक पाठशालाएं भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी उनके पुनर्निर्माण के लिए भी 3 करोड़ रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछली बरसात में सर्वाधिक नुकसान द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार का पूरा ध्यान दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास करने की ओर है। यहां बरसात से जो भी नुकसान हुआ है उसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने इस अवसर पर बताया कि कौल सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री रहते सर्वाधिक स्वास्थ्य संस्थान उनके विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में खोले थे। 90 प्रतिशत उठाऊ पेयजल योजनाएं उनके सिंचाई मंत्री रहते उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में शुरू की हैं। वह सदा उनके आभारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का घमंड चूर हो चुका है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा केवल 240 सीटों पर सिमट गई है। उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा की चार सीटें जीतने पर हिमाचल में भाजपा के धनबल की हार हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही 150 कॉलेजों में से 105 में प्रधानाचार्य के पदों और 630 सहायक प्राचार्यों के पदों को भरा है। अगले महीने में सीधी भर्ती और प्रमोशन के आधार पर 1200 से अधिक स्कूल लेक्चररों के खाली पद भर दिए जाएंगे। मंडी जिला के सभी स्कूलों में जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक है वहां पर एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति बहुत जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी और निजी स्कूलों में जो अंतर है उसे खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने शिक्षा मंत्री द्वारा सरनाहुली मेले का शुभारम्भ करने और द्रंग विधानसभा के क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के शिलान्यास करने के लिए शिक्षा मंत्री का धन्यवाद किया।

शिक्षा मंत्री ने इस दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दलों को 15-15 हजार रुपये भी स्वीकृत किए।

विश्व बैंक की टीम ने बागवानी मंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। टॉस्क टीम लीडर बेकजोड शैमसेव के नेतृत्व में विश्व बैंक की टीम ने बागवानी विकास परियोजना के सम्बंध में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भेंट की। बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी विशेषकर सेब उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने विश्व बैंक की टीम से इस परियोजना के लिए वांछित भूमि का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करने को कहा। उन्होंने इस परियोजना की सफलता के लिए हरसम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान विश्व बैंक की टीम ने बागवानी मंत्री को परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने प्रदेश सरकार, बागवानी विभाग तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं विधायन निगम एचपीएमसी की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में बागवानों तथा किसानों के हित के लिए अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। इस दौरान फलों का बीमा तथा संरक्षण पर भी चर्चा की गई।

15 सदस्यीय विश्व बैंक की टीम हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास परियोजना के लिए दौरे पर है। इस अवसर पर विश्व बैंक टीम के सदस्य डॉ. अरविंद झाम्ब, जेरार्ड बॉएल, डॉ. इवाना डयूलिक-मार्कोविक तथा धीरेन शेठ उपस्थित थे।

जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या नीट और जेईई का विकल्प नहीं हो सकता

इस बार नीट की परीक्षा को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है। आरोप लग रहा है कि शायद इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आरोप का आधार एक अभ्यार्थी अंजलि पटेल की प्लस टू की वायरल हुई अंक तालिका है। वायरल अंक तालिका के मुताबिक अंजलि प्लस टू के कैमिस्ट्री और फिजिक्स पेपरों में फेल है जबकि नीट में उसका स्कोर 720 में से 705 रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट की परीक्षा पर उठते सवालों की जांच की मांग की है। देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिये जेईई और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिये नीट की परीक्षाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 से आयोजित की जा रही है और इन परीक्षाओं के संचालन के लिए वर्ष 2017 से एनटीए का गठन किया गया है। जब से इन संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं का चलन शुरू हुआ है उसी के साथ इन परीक्षाओं के लिये कोचिंग संस्थानों का चलन भी आ गया है।

देश के हर कोने में कोचिंग संस्थान या इनकी ब्रांचें उपलब्ध हैं। इन संस्थानों में इन परीक्षाओं की कोचिंग के लिये बच्चों से लाखों की फीस ली जा रही है। इन दिनों इन परीक्षाओं में कोचिंग के लिये दाखिला लेने के लिये इन संस्थाओं के विज्ञापनों से अखबारों के पन्ने भरे हुये मिल जायेंगे। हर संस्थान का यह दावा मिल जायेगा कि उसके संस्थान से इतने बच्चे परीक्षा के टॉप में पास होकर प्रवेश ले चुके हैं। यह दावे कितने सही होते हैं इसकी पड़ताल करने का समय कितने अभिभावकों या बच्चों के पास होता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि हर अभिभावक और बच्चा कोचिंग लेकर इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है। कई बार बच्चों पर यह परीक्षा पास करने का इतना मनोवैज्ञानिक दबाव और तनाव होता है कि बच्चे आत्महत्या तक करने पर आ जाते हैं। राजस्थान के कोटा में शायद कोचिंग संस्थानों का हब है ओर वहीं से सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आये हैं। एक बार राजस्थान विधानसभा में भी यह मामला गूंज चुका है और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस पर कई सनसनी खेज खुलासे करते हुये परीक्षा और कोचिंग संस्थानों पर एक बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगाये थे। अब जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जा पहुंचा है और इसमें सीबीआई की गहन जांच की मांग की जा रही है तब इसके विकल्पों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश का आधार प्लस टू पास होना रखा गया है। इन संस्थानों में भी प्लस टू ही कोचिंग का आधार है। लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं जो प्लस टू के बिना ही कोचिंग में प्रवेश दे देते हैं। ऐसे प्रवेश को डम्मी प्रवेश की संज्ञा दी जाती है। बच्चा किसी स्कूल से प्लस टू करने के बजाये डम्मी प्रवेश लेकर ऐसे कोचिंग संस्थानों से ही प्लस टू का प्रमाण पत्र हासिल कर लेता है। क्योंकि इन संसथानों ने किसी न किसी मानरूता प्राप्त स्कूल से आइअप कर रख होता है। इसलिये पहला फर्जीवाड़ा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला लिये बिना ही प्लस टू पास करने का प्रमाण पत्र हासिल करना हो जाता है। यह कोचिंग संस्थान किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित शैक्षणिक संस्थान तो होते नहीं हैं। फिर इनके द्वारा डम्मी प्रवेश से रेगुलर प्लस टू का प्रमाण पत्र मिल जाना अपने में ही फर्जीवाड़ा सिद्ध हो जाता है। ऐसे डम्मी प्रवेशों की गहन जांच किया जाना बहुत आवश्यक है।

इसलिये इस समस्या का एक निश्चित हल खोजा जाना आवश्यक हो जाता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश का मूल आधार प्लस टू पास होना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा प्लस टू किये बिना ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करके ही प्रवेश का पात्र बन जाये। जब ऐसा नहीं है तो फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने का वैधानिक लाभ क्या है? यह प्रवेश परीक्षा तो अपनी सुविधा के लिये एक साधन मात्र है। जब 2012 तक ऐसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कोई प्रावधान था ही नहीं तो उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने पर क्या एन ए टी कोई सर्टिफिकेट जारी करता है शायद नहीं। ऐसे में जब मूलआधार ही प्लस टू है तब क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि देशभर में प्लस टू का पाठयक्रम एक बराबर करके पूरे देश में एक जैसे ही प्रश्न पत्र जारी किये जायें। इस तरह प्लस टू का जब देश भर में पाठयक्रम और परीक्षा प्रश्न पत्र एक जैसे ही होंगे तो फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता ही क्यों रह जायेगी। उसी की मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल जायेगा इसमें कोई पेपर लीक या फर्जीवाड़े की गुंजाइश ही नहीं रह जायेगी। यह सुझाव एक सार्वजनिक बहस और सर्व सहमति के लिये दिया जा रहा है। आज की परिस्थितियों में इस पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है।

नरेन्द्र मोदी व भाजपा को नैतिकता की पाठ पढ़ाने से पहले संघ को अपने गिरेवान में झांकना चाहिए

गौतम चौधरी

संसदीय आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर हिन्दू राष्ट्र विचार परिवार का प्रतिनिधि संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बेहद संजीदा दिख रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। फिलहाल जो बातें समझ में आ रही है वह एकदम सीधा और सरल है। मसलन, संघ और विचार परिवार के संगठन में बड़े पैमाने पर जड़ता आ गयी है। आम जनता, भारतीय जनता पार्टी और संघ को अलग-अलग करके नहीं देखती है। इसलिए भाजपा में जो भी हो रहा है, उसका प्रभाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पड़ना तय है। आम लोग तो यही समझते हैं कि भाजपा जो भी कर रही है उसमें संघ की ही भूमिका है। हालांकि इसमें बहुत हद तक सत्यता भी है।

भाजपा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यदि इतिहास को देखें तो अतीत में जब कभी भाजपा सत्ता में रही, संघ उनकी कुछ नीतियों को लेकर आलोचना जरूर करता रहा, लेकिन विगत एक दशक से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा देश की सत्ता में है, संघ के किसी अधिकारी ने भाजपा की किसी नीति की आलोचना नहीं की, जबकि भाजपा की सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए जो संघ की नीतियों के खिलाफ जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत नागपुर के एक कार्यक्रम में मोटे तौर पर चार ऐसी बातें कही, जो विगत कई दिनों से सुर्खियां बटोर रही है। उनकी पहली बात यह है कि विगत लगभग एक वर्ष से मणिपुर जल रहा है लेकिन वहां शांति के उपाय नहीं हो पा रहे हैं। मोहनराव जी ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। यह राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए लेकिन इस मामले पर संघ ने क्या किया? विगत एक वर्ष में संघ के दो अखिल भारतीय कार्यक्रम हुए और दोनों में प्रस्ताव भी पारित हुए लेकिन कहीं मणिपुर की अशांति का जिक्र नहीं आया, जबकि संघ ऐसे राष्ट्रीय समस्याओं पर पहले अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्ताव पारित करता रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विगत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि वर्ष में देश व विदेश के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी दो वार एक स्थान पर मिलते हैं। एक प्रतिनिधि सभा के मौके पर और दूसरा अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक को लेकर। इन दोनों मौकों पर संघ अपनी रणनीति तय करता है। इन दोनों मौकों पर संघ समसामयिक मुद्दों पर प्रस्ताव भी पारित करता रहा है लेकिन मणिपुर जैसे राष्ट्रीय मुद्दे संघ की न तो प्रतिनिधि सभा का मुद्दा बना और न ही कार्यकारी मंडल में इसे उठाया गया। यदि संघ इस मामले को लेकर इतना ही गंभीर है तो पहले अपने बीच इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं किया?

दूसरी बात यह है कि संघ विचार परिवार में 50 से अधिक संगठन काम करते हैं। पूर्वोत्तर को लेकर संघ पहले से गंभीर रहा है लेकिन पता नहीं क्यों संघ मणिपुर के मामले में चूक गया। संघ गंभीर होता तो वहां के लिए अपने स्तर पर एक समिति बनाने और अपने स्तर पर वहां की समस्या के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाता लेकिन यहां भी संघ नेतृत्व कुछ करने में असफल रहा।

मोहनराव जी ने नेतृत्व में अहंकार और अहम बढ़ने की बात कही। इस मामले पर तो संघ को सबसे पहले अपने गिरेवान में झांकना चाहिए। केएस सुदर्शन के कार्यकाल तक आम स्वयंसेवकों की पहुंच सरसंघचालक तक हो जाया करती थी। सरकार्यवाह भैयाजी जोशी के कार्यकाल तक आम स्वयंवेक अपनी बात शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाने में कामयाब हो जाते थे लेकिन आज आम स्वयंसेक को विभाग प्रचारक तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना होता है। प्रचारकों का शाखा से नाता टूटता जा रहा है। संघ की शाखा जो संगठन की पहचान थी वह एक औपचारिकता मात्र बन कर रह गयी है। संघ के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक अहम के मद में चूर दिखते हैं। मोहनराव जी को अन्य की अपेक्षा अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है।

रही बात लोकतंत्र की मर्यादा का तो जब पूरे देश में मॉब लिंचिंग को लेकर हाय तौबा मचार था उस वक्त संघ के एक बड़े अधिकारी ने बयान जारी किया कि यदि मुसलमान गाय मारते रहेंगे तो मॉब लिंचिंग होता रहेगा। संघ को उसी वक्त इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए था और किसी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का बयान कितना खतरनाक हो सकता है इसकी कल्पना कर लेनी चाहिए थी। विपक्ष और प्रतिपक्ष पर भी मोहनराव जी ने बातें कही। इसी प्रकार के चुनाव 2019 में भी हुए। मोदी के नेतृत्व में प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव युद्ध मोड में लड़े गए लेकिन संघ के किसी पदाधिकारी ने इस विषय पर मोदी और भाजपा नेतृत्व को टोकने तक की जहमत नहीं उठायी।

मोदी के सभी कामों में संघ का मौन समर्थन रहा है। मोदी के किसी निर्णय का संघ ने आज तक विरोध नहीं किया। हालांकि मोदी ने कुछ ऐसे बड़े काम किए जो संघ की नीतियों का आधार है और संघ विचार परिवार के संगठनों ने उस पर आन्दोलन भी चलाए लेकिन नोटबंदी, किसान बिल, मजदूर बिल, विदेशी कंपनियों के लिए दरबाजा खोलना आदि तो संघ की नीतियों के खिलाफ था, बावजूद इसके संघ मौन क्यों रहा?

संघ के सरसंघचालक मोहनराव जी के बयान, संघ की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। संघ अब कमजोर हो रहे मोदी से पल्ला झारना चाहता है। वैसे भी मोदी कभी संघ की पसंद नहीं रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री काल से ही संघ और मोदी में ठनी हुई है। या ऐसा कहें कि मोदी जब संघ के प्रचारक थे तब भी संघ की पसंद नहीं रहे। मोदी अपने नेतृत्व क्षमता और भाग्य से आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है। मोदी के पूरे प्रधानमंत्री काल में संघ के अधिकारी और संघ समर्थित व्यापारी, ठेकेदार जबरदस्त तरीके से उप त हुए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। मोदी चूकि खुद प्रचारक रहे हैं इसलिए संघ की कमजोरियों को भी जानते हैं। इसलिए संघ को मोदी और मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा पर नैतिक प्रहार से पहले अपने गिरेबान में भी एक बार झांकना चाहिए।

17वीं किस्त से 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जून 2024 को पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कई राज्य मंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और देश भर के 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों के 2.5 करोड़ से अधिक किसान शामिल होंगे।

50 चयनित कृषि विकास केंद्रों (केवीके) पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। इन केंद्रों पर कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों, कृषि क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु अनुकूल कृषि आदि के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि वे अपने पीएम-किसान लाभार्थी की स्थिति, भुगतान की स्थिति आदि की जांच कैसे करें, किसान-ई-मित्र चैटबॉट का उपयोग कैसे करें। केंद्रीय मंत्री क्षेत्र की प्रशिक्षित कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 जून 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका और किसानों के प्रति पीएम मोदी के अटूट सहायता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कृषि हमेशा से प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है। 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना ने किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करके काफी लाभ पहुंचाया है। उन्हें कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि के माध्यम से आज भी सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और देश के खाद्य भंडार को बनाये रखने में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कृषि और किसानों की सेवा को भगवान की पूजा के समान बताया। कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार का समर्पण, उसके निरंतर प्रयासों और आगामी 100-दिवसीय योजना सहित रणनीतिक योजनाओं से स्पष्ट है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई है, जो उच्च आय की स्थिति के कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

कृषि सखियों को कृषि पैरा-विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और अनुभवी किसान हैं। कृषि सखियों को पहले से ही विभिन्न कृषि पद्धतियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त है, जिससे वे साथी किसानों को प्रभावी ढंग से सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज तक, 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा-विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में प्रमाणित किया गया है।

प्रशासन सुधारों में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण को शामिल किया जाएगा

शिमला। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैन्शन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि 'प्रशासन सुधारों में बुजुर्ग नागरिकों और पेंशनभोगियों सहित नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण को शामिल किया जाएगा।'

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन का दृष्टिकोण और उनके नेतृत्व में हमारा मंत्रालय पिछले दशक में शुरू किए गए सुधारों को जारी रखेगा।''

डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, नागरिक सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के केंद्र में हैं और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करके, एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाकर, नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के साथ डिजिटल शासन को बढ़ाकर नागरिकों का कल्याण के संकल्प को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के जीवन में आसानी लाना है।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को समकालिक समयसीमा के साथ भर्ती नियमों और सेवा नियमों की बहुलता को तर्कसंगत बनाने की दिशा में काम करने और इसे भविष्य के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल तकनीक को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। डॉ. सिंह ने सरकारी विभागों की दक्षता बढ़ाने के लिए अद्वितीय योग्यता निर्माण उत्पाद बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 'सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए सुधारों को जारी रखना और प्रशिक्षण संरचनाओं और कार्यप्रणाली में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है।'

डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, जनरल एआई, मशीन लर्निंग (एमएल), ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग हमारे नए युग के सुधारों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लोक सेवकों के लिए आई-गॉट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और मिशन कर्मयोगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक स्व-प्रेरित वातावरण बनाना है। समीक्षा करते समय उन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली में डिजिटल लर्निंग लैब के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली, जिसका उद्घाटन डॉ. सिंह ने डीओपीटी मंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में किया था। उन्होंने ई-लर्निंग और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को उनके करियर की प्रगति का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया। उन्होंने तकनीकी रूप से तेजी से बदलती दुनिया में फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अच्छे प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों और विभागों को पुरस्कृत करना और सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही बढ़ाना हमारा केन्द्रित क्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने उत्कृष्टता केंद्र की पहचान और निर्माण के साथ क्षमता निर्माण के लिए अत्याधुनिक भौतिक और डिजिटल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और आवास सर्वोत्तम संकाय के निर्माण पर भी अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि 'हमें क्षमता निर्माण को और अधिक जैविक बनाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।'

केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रिवंसेस -डीएआरपीजी) की समीक्षा करते हुए कहा की 'हमें सरकारी विभागों के बीच सहकारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बार-बार दोहराने के लिए राज्यों के लिए पहले से विद्यमान सूचकांक के अनुरूप केंद्रीय मंत्रालयों के लिए एक सुशासन सूचकांक बनाना चाहिए।' उन्होंने विश्व भर में सबसे अच्छे शिकायत निवारण तंत्र के रूप में पहचाने जाने वाले केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की सफलता पर डीएआरपीजी के प्रयासों की भी सराहना की और इसे अन्य क्षेत्रों में भी जारी रखने और दोहराने का निर्देश दिया। उन्होंने शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षेत्रीय कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने नए युग की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सतर्कता मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक संरचित तंत्र तैयार करने का निर्देश भी दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा, 'पेंशन नियमों को एकीकृत करके और जीवनयापन में आसानी लाकर वरिष्ठ नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हमारे विभाग की मार्गदर्शक शक्ति है। 'केंद्रीय मंत्री ने पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान की सफलता की सराहना की और उन्हें इसे और अधिक उत्साह और शक्ति के साथ आगे जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को विभाग की भविष्य की रणनीति पर निर्देश देते हुए कहा कि 'हमें बैंकों के साथ भविष्य पोर्टल का एकीकरण जारी रखना चाहिए।' मंत्री महोदय के अनुसार पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनके सेवानिवृत्त वर्षों को सुगम बनाने के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग) कार्यशालाओं का आयोजन जारी रखा जाना चाहिए। डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार भाषा सहायता देने वाली होनी चाहिए न कि बाधा और इस प्रकार नागरिकों तक उनकी मातृभाषा में पहुंचने के लिए भाषिणी के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

इस बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी0 की सचिव एस. राधा चौहान और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) एवं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के सचिव वी.श्रीनिवास के साथ-साथ तीनों विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना का 'डी5' मोटर साइकिल अभियान शुरू

शिमला। कारगिल युद्ध के वीरों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में, भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। यह अभियान हमारे वीर सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान का प्रदर्शन और उनकी विरासत का सम्मान करता है।

आठ मोटरसाइकिलों की तीन टीमों ने देश के तीन कोनों-पूर्व में दिनजन, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में धनुषकोडि से इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की है। ये साइकिल सवार विभिन्न इलाकों और चुनौती भरे मार्गों को पार करेंगे, जो हमारे सशस्त्र बलों की एकता और लचीलेपन का प्रतीक है। अपने रास्ते में, सवार कारगिल यद्ध के नायकों, दिग्गजों और वीर नारियों से संपर्क करेंगे जो उनके रास्ते में आने वाले विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं। वे मार्ग में विभिन्न युद्ध स्मारकों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जन जागरूकता बढ़ाएंगे और युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेंगे।

पूर्वी मार्ग में दिनजन से दिल्ली तक की आवाजाही शामिल है, जो लगभग 2,489 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जोरहाट, गुवाहाटी, बिनागुरी, कटिहार, दानापुर, गोरखपुर, लखनऊ और आगरा से गुजरेगी।

पश्चिमी मार्ग में द्वारका से धांगधरा, अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और अलवर होते हुए दिल्ली तक की आवाजाही शामिल है। इस प्रकार यह लगभग 1,565 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

दक्षिणी मार्ग में धनुषकोडि से दिल्ली तक मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, अनंतपुर, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, ग्वालियर और अलवर होते हुए लगभग 2,963 किलोमीटर की आवाजाही शामिल है।

ये टीम 26 जून को दिल्ली में एकत्र होंगी और दो अलग-अलग मार्गो से द्रास के लिए रवाना होंगी। एक मार्ग अंबाला, अमृतसर, जम्मू, ऊधमपुर और श्रीनगर होते हुए 1,085 किलोमीटर की

दूरी तय करता है जबकि दूसरा चंडीमंदिर, मनाली, सरचू, न्योमा, तंगत्से और लेह के माध्यम से 1,509 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस अभियान का समापन में द्रास के गन हिल में होगा, जो कारगिल युद्ध के दौरान अपने रणनीतिक महत्व के लिए इतिहास में अंकित एक स्थान है। अभियान का यह अंतिम चरण न केवल बहादुरी के मार्ग पर फिर से आगे बढ़ेगा, बल्कि यह हमारे सैनिकों की अथक भावना और समर्पण की याद दिलाने का भी काम करेगा।

सभी प्रमुख स्थानों पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और विशिष्ट अतिथियों को शामिल करने के लिए प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में "लैग ऑफ और "लैग-इन समारोह आयोजित किए जाएंगे, जो इन सवारों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले उद्देश्य का अभिनंदन करेंगे। कारगिल युद्ध के दिग्गजों और वीर नारियों को भी युद्ध के दौरान उनके बलिदान और दृढ़ संकल्प को मान्यता देते हुए सम्मानित किया जाएगा।

इस अभियान का नेतृत्व तोपखाने की रेजिमेंट कर रही है जिसने ऑपरेशन विजय में सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सशस्त्र बलों के पक्ष में स्थिति बदलने में तोपखाने की सटीकता, मारक क्षमता और रणनीतिक समर्थन महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। जैसे-जैसे सवार देश के कोने-कोने की यात्रा करेंगे, वे अपने अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति की कहानियों को साथ ले जाएंगे। यह अभियान केवल श्रद्धांजलि ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की स्थायी भावना का प्रतीक भी है।

मुख्यमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के स्थापना कार्य की प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदार बनेगी तथा इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1923 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की यह परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार 10 वर्षो तक परियोजना की परिचालन लागत वहन करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में 5 एमएलडी क्षमता वाला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, स्टार्म वॉटर ड्रेन नेटवर्क, कॉमन साल्वेंट स्टोरेज, रिकवरी एवं डिस्टिलेशन सुविधा, स्ट्रीम उत्पादन संयंत्र, आधुनिक प्रयोगशाला जांच केन्द्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र, संकटजनक संचालन लेखा केन्द्र और उत्कृष्टता केन्द्र की सुविधा होगी।

इसके अतिरिक्त पैदल पथ, कैंटीन, अग्निशमन केन्द्र, प्रशासनिक ब्लॉक जैसी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा तथा स्थल विकास कार्य भी किए जाएंगे। उन्होंने उद्योग विभाग को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने, परियोजना को धरातल पर लाने के लिए किसी भी प्रकार की अड़चन को दूर करने तथा सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क को अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि यह बल्क ड्रग पार्क राजस्व सृजन में सहायक होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाएगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित बहुमूल्य सुझाव दिए।

कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और ऊना दुग्ध संयंत्रों की क्षमता 20-20 हजार लीटर की जाएगी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादक प्रसंघ मिल्कफेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ढगवार दुग्ध संयंत्र के निर्माण से जुड़ी सभी

प्रक्रियाएं और इसका निर्माण समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे क्षेत्र की आर्थिकी को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध संयंत्र कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और दुग्ध संयंत्र ऊना की क्षमता 20-20 हजार लीटर की जाए। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन समितियों के पंजीकरण में तेजी लाई जाये और पंजीकरण प्रक्रिया में किसानों को हर सम्भव सहायता प्रदान की जाये। उन्होंने किसानों के क्षमता निर्माण और दुग्ध गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने दुग्ध विपणन प्रक्रिया व इसके परिवहन का युक्तिकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिल्कफेड के ट्रेडमार्क हिम का भारत सरकार द्वारा पंजीकरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 1148 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं जिनके 47905 सदस्य हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 19388 है। वर्तमान में प्रदेश में 11 दुग्ध उत्पादन संयंत्र और 116 बल्क मिल्क कूलर स्थापित हैं। मिल्कफेड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से दुग्ध एकत्रीकरण के गुणवत्ता मापदण्डों में आशातीत बढ़ौतरी हुई है।

कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि दुग्ध गतिविधियों को सशक्त करने के लिए समितियों का पंजीकरण नितांत आवश्यक है। इससे किसानों का सशक्तिकरण होगा। उन्होंने कहा कि मिल्कफेड को सशक्त करने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

डेढ़ वर्ष के भीतर तैयार होगा लुथान में बनने वाला मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला

कांगड़ा के लुथान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसरों को निश्चित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 132 करोड़ रुपये से 400 आश्रितों के लिए बनाये जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई, 2024 से पूर्व आरम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस परिसर को डेढ़ वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में बनने वाले परिसर का नक्शा व निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इन परिसरों में अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल नारियों एवं वृद्धजनों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने इन परिसरों को अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी आवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे अनाथ बच्चों को होस्टल की सुविधा न मिलने पर प्रदेश सरकार किराए के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने विभाग को इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को सुदृढ़ करने के दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और तीन साल की उम्र तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी के बजाये ड्राई फ्रूट देने की संभावनाओं को भी तलाशा जाना चाहिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधवाओं तथा एकल नारियों को घर निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया है। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में आदर्श राज्य स्तरीय नशा निवारण केंद्र बनाया जाएगा। जिसके लिए निविदा प्रक्रिया 20 जुलाई, 2024 तक पूर्ण की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला सोलन में कंडाघाट क्षेत्र के टिक्करी में लगभग 300 दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्मित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने इस अवसर पर बहुमूल्य सुझाव साझा किए।

मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए 23 जून 2024 तक करें आवेदन

शिमला/शैल। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के आधार पर मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत 23 जून, 2024 तक मेधावी विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। निदेशक उच्चतम शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा ने बताया कि प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के पात्र संस्थानों से सीएलएटी /नीट/ आईआईटी- जेई- एएफएमसी/ एनडीए व यूपीएससी /एसएससी बैंकिंग तथा इन्श्योरेंस व रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 12वीं स्तर के 280 अभ्यर्थियों तथा स्नातक स्तर के 120 अभ्यर्थियों का इस योजना के तहत मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12वीं तक के इच्छुक विद्यार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक उच्चतर शिक्षा के पास डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से तथा स्नातक स्तर के छात्र-छात्राएं अपना आवेदन पत्र पीडीएफ फॉरमेट में अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक, महाविद्यालय, शिक्षा निदेशालय के पास डाक द्वारा या ई-मेल medh.protsahan /gov.in पर 23 जून 2024 तक कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन अमान्य होंगे।

उन्होंने कहा कि एक ई-मेल से केवल एक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी शिक्षा निदेशक उच्चतर, हिमाचल प्रदेश की वेबसाई www.education.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तीन प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में तीन विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई 2024 को होने वाले उप-चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रणनीति बनाई गई।

कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रभावशाली नेतृत्व की सराहना की और विश्वास जताया कि आगामी उपचुनावों में पार्टी सभी तीन विधानसभा क्षेत्रों में विजय हासिल करेगी। बैठक में हाल ही में छः विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में चार सीटें जीतने के लिए प्रदेश के लोगों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इस जीत के फलस्वरूप विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। बैठक के दौरान सभी विधायकों ने कहा कि यह जीत डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियों व योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त जानकारी दी गई कि वर्ष 2019 में आयोजित

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में हुए 27.53 प्रतिशत मतदान के मुकाबले इस बार हुए लोकसभा चुनाव में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 41.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

कांग्रेस विधायक दल ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा द्वारा चलाये गये ऑप्रेशन लोटस तथा अन्य दांव पेचों की निंदा की। सभी विधायकों ने ऐसे प्रयासों को विफल करने और राजनीतिक मर्यादा को बनाये रखने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल भविष्य में भी भाजपा द्वारा राजनैतिक साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित व तैयार हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रीगण तथा विधायकगण भी बैठक में उपस्थित थे।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने ईद-उल-जुहा की मुबारकबाद दी

शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद (बकरीद) की मुबारकबाद दी।

राज्यपाल ने अपने सन्देश में सभी मुस्लिम भाई-बहनों को मुबारकबाद देते हुए उनके खुशहाल एवं समृद्ध जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक यह त्यौहार समाज को शांति, करूणा और एकता का सन्देश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आहवान किया।

प्रदेश में बढ़ते जल संकट पर सरकार खामोश:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी वक्तव्य में कहा कि अब प्रदेश से आचार संहिता हट गई है। इसलिए सरकार द्वारा करवाये जाने वाले किसी भी प्रकार के विकास कार्य करने पर किसी भी तरह की रोक भी नहीं है। अत: अब सरकार डेढ़ साल से बंद पड़े विकास कार्यो की शुरुआत करे। जब से कांग्रेस सत्ता में आयी है तब से विकास के सारे काम रूके हुए हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल के चलते हुए काम बंद हैं। सड़कों से लेकर पुलों के काम रूके हुए हैं। आपदा के बाद से सड़कों पर पड़ा मलबा नहीं उठाया जा सका है। जिससे लोगों की बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करे। अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश जलापूर्ति के भारी संकट से गुजर रहा है। पानी की सप्लाई पूरे प्रदेश में प्रभावित है। टूरिस्ट सीजन चल रहा है लेकिन हर जगह पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकारी द्वारा गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर चार से पांच दिन में पानी आ रहा है। कई जगहों पर हालात और भी बुरे हैं। पूरे प्रदेश का यही हाल है लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से ख़ामोश है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह पहले से तय था कि गर्मी के मौसम पानी की खपत बढ़ती है। टूरिस्ट सीजन की वजह से प्रदेश में भारी संख्या में लोग आते हैं, जिस वजह से होटल्स में भी पानी की खपत बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए ख़ास प्रबंध होने चाहिए। लेकिन सरकार द्वार इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गयी। इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। जिसका नतीजा सामने है। प्रदेश के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलापूर्ति में किसी तरह की समस्या न आने पाये यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अग्रिम योजना बनाये। संभावित चुनौतियों के लिए सरकार तैयार रहे। इस तरह से प्रदेश के लोगों को हर ज़रूरी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। सरकार अपना दायित्व निभाये, जिससे आम लोगों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

कांग्रेस की सरकार में जनता समग्र विकास के इंतजार में : सत्ती

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कांग्रेस सरकार में कुप्रबंधन चरम सीमा पर है, जनता त्रस्त है और सरकार मित्रों को एडजस्ट करने में मस्त है। हाल ही में बिजली उपमंडल नादौन के तहत धनेटा स्थित बिजली बोर्ड के कार्यालय में एक कनिष्ठ अभियंता ने शराब के नशे में धुत होकर लोगों व अपने सीनियर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। जिस पर कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचने की बात तो यह है की इस सरकार में यह नौबत बार बार क्यों आती है। इस प्रकार का गैरजिम्मेदार व्यवहार माफी के काबिल नहीं है और प्रदेश को शर्मसार करता है।

उन्होंने कहा की सस्ते राशन के डिपुओं से सरसों का तेल, रिफाइंड और चीनी गायब हो गई है। इस कारण उपभोक्ताओं को जून में आधा-अधूरा राशन मिल रहा है। बिलासपुर में करीब 1.77 लाख राशन कार्ड धारकों को जून में महंगे दामों पर बाजार से चीनी और तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका कारण खाद्य तेल का टेंडर नहीं होना और चीनी के रेट को सरकार से स्वीकृति नहीं मिलना है। गोदामों में अभी तक सरसों तेल, रिफाइंड तेल और चीनी की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। यह है वर्तमान कांग्रेस सरकार की सच्चाई, ना जाने हर मुश्किल की घड़ी में सरकार किधर गायब हो जाती है। जब जब जनता पर मुसीबत आती है तब तब सरकार को लेंस से ढूंढना पड़ता है।

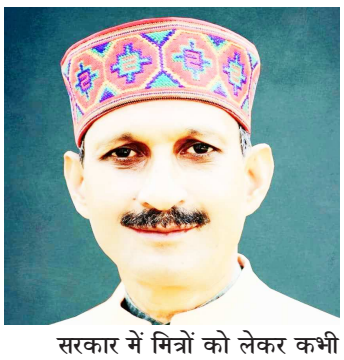

सरकार में मित्रों को लेकर कभी कोई भी बड़ी घोषणा हो सकती है पर जनता के लिए जनहित के कार्य, प्रदेश में विकास के कार्य सभी रुके पड़े है। जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से जनता समग्र विकास के इंतजार में है। विधायकों, जन प्रतिनिधियों यहां तक की पंचायत के प्रधान भी इंतजार में है की उनके क्षेत्र में कुछ विकास का काम होगा। इस सरकार में सभी को केवल निराशा ही हाथ लगी है।

हिमाचल प्रदेश में झूठ की राजनीति नहीं चलती:सुधीर

कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से काम किया: लखनपाल

शिमला/शैल। भाजपा के नवनियुक्त विधायक सुधीर शर्मा और इन्द्रदत्त लखनपाल का विधानसभा पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और समस्त विधायक दल ने उनका

स्वागत एवं अभिनंदन किया। जयराम ठाकुर और भाजपा के विधायकों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके उपरांत दोनों विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली।

इस अवसर पर सुधीर शर्मा ने कहा की कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हारी है और हमने खुद धर्मशाला में कांग्रेस को हराया है। हिमाचल प्रदेश में झूठ की राजनीति नहीं चलती और कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति की है।

उन्होंने कहा की यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने और केंद्र सरकार ने मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दूसरी बार बने है। सभी नेताओ और कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं।

सुधीर ने कहा की केंद्र ने मोदी 3.0 सरकार में भी वित्त मंत्रालय मिलने के तुरंत बाद निर्मला सीतारमण ने निर्णय लिया है कि राज्यों को जून 2024 के टैक्स हस्तांतरण के नियमित रिलीज अमाउंट के अलावा एक अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी, जो कि एक लाख 39 हजार 750 करोड़ रुपए है। राज्यों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए इस अमाउंट के साथ 10 जून, 2024 तक कुल दो लाख 79 हजार 500 करोड़ रुपए राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन किये गये हैं। हिमाचल को केंद्र ने हमेशा उसका हक दिया है, पर वर्तमान सरकार ने हमेशा प्रदेश पर आर्थिक बोझ बड़ाने का काम किया है।

इन्द्रदत्त लखनपाल ने कहा की प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में दो बड़े निर्णय लिये। पहला निर्णय देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ मकान बनाने का और दूसरा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का। यह दिखाता है की केंद्र सरकार किस सकारात्मक रूप में देश को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा की प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने केवल बदले की भावना से काम किया है जो की प्रदेश हित में नहीं है।

कांग्रेस सरकार में कुप्रबंधन हावी:गोविंद

शिमला/शैल। भाजपा पूर्व मंत्री एवं संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद ठाकुर ने कहा की हिमाचल सरकार कुप्रबंधन में टॉपर है और निरंतर जनता को कर रही परेशान कर रही है। जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है तब से केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में कुप्रबंधन हावी है, पर पूरी सरकार मस्त हो रखी है।

गोविंद ने कहा की पानी सप्लाई की तीन-तीन स्कीमें होने के बाद भी ग्रामीण पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। आलम यह है कि चिलचिलाती गर्मी के बीच ग्रामीणों को 5 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। मंडी जिला के पंडोह के साथ लगती स्योग पंचायत के तीन पीपल गांव में 200 के करीब घर हैं और यहां 500 से अधिक लोग रहते हैं। बीते 20 दिनों से पानी की सप्लाई न आने से सभी ग्रामीण बेहाल हैं।

पूर्व मंत्री ने बताया की बीते 20 दिनों से यहां पर ग्रामीण वासियों को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। तीन पीपल गांव के लिए पानी की तीन-तीन स्कीमें हैं, वर्ष 1997 में यहां एक हैंडपंप स्थापित किया गया था। मोटर लगाकर इससे पानी निकाला जाता था और आसपास के लोग भी यहां से पानी ले जाते थे लेकिन अब यह सूख गया है। इसके अलावा बीबीएमबी और जल शक्ति

विभाग की स्कीमें भी यहां के लिए हैं लेकिन वे भी सूख गई हैं।

उन्होंने कहा की हिमाचल सरकार किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकाल ही नहीं पा रही है। केवल मात्र सत्ता बचाने का प्रयास कर रही है और उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। पानी की समस्या हो, प्रदेश में जंगल आग की समस्या हो, कानून व्यवस्था को सुधारने की समस्या हो पर इस सरकार से किसी भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। केवल मात्र यह सरकार ही समस्या बन कर रह गई है।

मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

शिमला/शैल। प्रदेश में आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी उपायुक्तों ने आगामी सीजन को लेकर जिला स्तर पर की गई तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नदी किनारे रह रहे प्रवासी मजदूरों को अन्य स्थानों पर बसाया जाए ताकि जानमाल की हानि न हो। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री का भंडारण करने के निर्देश दिए ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को अनाज की कमी न हो।

बैठक में बांधों और नदियों में पानी का स्तर मापे जाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इसके लिए बांध प्राधिकरणों और केंद्रीय जल आयोग को साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने और अग्रिम चेतावनी प्रणाली को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। इसके लिए बांध प्राधिकरणों और केंद्रीय जल आयोग के साथ बैठकें आयोजित

की जाएंगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बांध प्राधिकरण अपनी मशीनरी और बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखें। उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे तिरपाल इत्यादि के दाम में बढ़ौतरी न हो।

विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने कहा कि सभी उपमंडलों को भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही सैटेलाइट फोन उपलब्ध करवाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त गत वर्ष कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में धसे स्थलों का दौरा करें और यदि स्थिति चिंताजनक है तो लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। वहीं मानसून सीजन में पहाड़ों की कटाई करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने अवगत करवाया कि 84 प्रदेश में इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून सामान्य रहेगा।

देहरा व नालागढ़ एवं जिला हमीरपुर में लागू होगी आदर्श आचार संहिता:मनीष गर्ग

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि कांगड़ा व सोलन जिलों के केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में ही आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी जिनमें उपचुनाव होने हैं।

उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत पूरे हमीरपुर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला के 10-देहरा विधानसभा क्षेत्र, सोलन जिला के 51-नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी जबकि इन जिलों के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आयेंगे।

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

बीबीएन क्षेत्र के भूजल में कैंसर कारक तत्वों का मिलना एक गंभीर मुद्दा

सरकार के निगरान तंत्र की कार्यशैली पर उठे सवाल

शिमला/शैल। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में कैंसर कारक तत्व हैं। यह तथ्य आईआईटी मण्डी के एक शोध अध्ययन के माध्यम से सामने आया है। एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र के भूजल स्रोतों को लेकर शिकायतें आ रही थी कि यहां का पानी पीने योग्य नहीं है। कई स्रोतों को बंद भी कर दिया गया था। बीबीएन क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। फार्मा उद्योग का तो यह देश का सबसे बड़ा हब है। यहां पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कामगार हजारों की संख्या में यहां काम करते हैं। इसके विस्तार के कारण इस क्षेत्र को पुलिस जिला भी बना दिया गया है। उद्योगों के सुचारू संचालन के लिये यहां पर उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग का ड्रग नियंत्रण यूनिट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय यहां स्थापित है। लेकिन इतना सारा प्रशासनिक तन्त्र यहां तैनात होने के बावजूद भी यहां का भूजल प्रदूषण के कारण कैंसर कारक हो जाये तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा चिंता का विषय और नहीं हो सकता। यहां पर निर्मित दवाओं के सैंपल टेस्ट एक लंबे अरसे से लगातार फेल होते जा रहे हैं। इस फेल होने पर सरकार कारण बताओं नोटिस जारी करने से आगे नहीं बढ़ सकी है। किसी उद्योग के उत्पादन पर रोक नहीं लगा सकी है। पिछले दिनों यहां हुये अग्निकांड में उद्योगों द्वारा अपनाये जा रहे अग्नि सुरक्षा कुप्रबंधों पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। अब यहां के भूजल में कैंसर कारक तत्वों के पाये जाने से प्रदूषण नियंत्रण की कार्य शैली पर गंभीर स्वाल खड़े कर दिये हैं। क्योंकि भूजल में इन तत्वों का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि उद्योग अपने वेस्ट को सही से ट्रीट न करके उसे खुले में फेंक रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला रसायन जब खुले में विसर्जित किया जायेगा तो वह निश्चित रूप से यहां की जमीन के अन्दर ही जमा हो जाएगा और भूजल को ही दूषित करेगा। जबकि भूजल पीने के लिये सबसे स्वच्छ माना जाता है। जब भूजल इस हद तक प्रदूषित मिलेगा तो निश्चित ही यहां पर प्रदूषण के मानकों की अनुपालन न होना प्रमाणित होता है। बल्कि यहां की ऐसी प्रभावित जमीन के हर उत्पादन की गुणवत्ता भी प्रश्नित हो जाएगी। दवाओं के सैंपल फेल होने पर आज तक दवा नियंत्रक विभाग के किसी भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कभी कोई कारवाई नहीं की गई है। अग्निकांड, अग्नि सुरक्षा उपायों के मानकों की अवहेलना सामने ला दी है परन्तु इसके लिए संबंधित तंत्र में से किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अब भूजल में कैंसर कारक तत्वों के पाये जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहां पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों की कोई जवाब देही तय नहीं हो पायी है जबकि प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी एक लंबे अरसे से यहां पर तैनात है। सरकारी तंत्र की इसी असफलता का प्रतिफल है की प्रदेश में कैंसर के रोगियों की संख्या में पिछले करीब एक दशक से 800% की वृद्धि हुई है। 2013 में ऐसे मरीजों की संख्या प्रदेश में 2419 थी जो 2022 में बढ़कर 17212 हो गयी है। इससे आने वाले समय में उद्योग नीति पर यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जायेगा कि ऐसी भयानक बीमारी की कीमत पर ऐसा औद्योगिक विस्तार प्रदेश हित में होगा या नहीं।

संस्थानों के बाद अब सुविधाओं पर तालाबाज़ी कर रही सरकार:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से वक्तव्य जारी कर कहा कि सरकार ने पहले संस्थानों पर तालाबाज़ी की और अब आम लोगों को मिल रही सुविधाओं पर तालाबाज़ी कर रही है। जिससे प्रदेश के लोग परेशान हों। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि आईजीएमसी में अब इंडोर टेस्ट बंद होने वाले हैं क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जांच में प्रयुक्त होने वाले रीजेंट्स का परचेज़ ऑर्डर ही नहीं दिया है। जिससे अस्पताल में भर्ती मरीज़ों की सामान्य से सामान्य जांच नहीं हो पाएगी। अस्पताल में भर्ती मरीज़ों और उनके परिजनों को अब निजी लैब से यह जांच करवाने के लिए भटकना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ्य व्यक्ति के लिए यह किसी आफ़त से कम नहीं है। इस तरह से बीमारी के समय में भी सुक्खू सरकार प्रदेश के लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। जिससे यह साफ़ है कि सुक्खू सरकार को प्रदेश के लोगों के सुख-दुःख से कोई मतलब नहीं हैं। यह सरकार पूरी तरह संवेदनहीन सरकार है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता सम्भालने के बाद से ही प्रदेश सरकार का प्रदेश के लोगों से कोई लेना देना नहीं हैं। प्रदेश सरकार का हर फ़ैसला जनविरोधी और प्रदेश के लोगों को परेशानी देने वाला रहा। सत्ता में आते ही डीज़ल के दाम बढ़ा देने से लेकर संस्थान बंद करने के फ़ैसले से सुक्खू सरकार की जनविरोधी मंशा साफ़ दिखी। सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। पूर्व सरकार की जनहित योजनाओं को भी बंद करने या उनके बजट रोकने का भी काम किया। सुक्खू सरकार के निशाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था भी रही। सत्ता में आने के बाद से लाखों लोगों के लिए लाइफ लाइन बनी हिमकेयर योजना का पैसा रोक दिया। जिससे लोगों का इलाज रुक गया। शेडयूल हुए ऑपरेशन रुक गये। लोगों की डायलिसिस रुक गई। इसके बाद सरकार ने अस्पतालों में निःशुल्क जांच करने वाली कंपनियों का पैसा रोक दिया । बार-बार पेमेंट का रिमाइंडर देने के बाद कंपनियों ने अस्पतालों में जांच भी बंद कर दी, तब भी सुक्खू सरकार तमाशाई बनी रही। अब अस्पताल में बेड पर लेटे हज़ारों मरीज़ों की इंडोर जांचे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था की जो उपेक्षा की जा रही है, वह दुःखद है। जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है उस समय उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेकिन वर्तमान सुक्खू सरकार उन्हें भी परेशान करने से बाज़ नहीं आ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, सरकार हर ज़रूरतमंद का सहारा होती है इसलिए वह लोगों की मदद करे उन्हें परेशान नहीं। भाजपा सुक्खू सरकार के जनविरोधी और मनमानी वाले फ़ैसलों का डटकर विरोध करेगी।